



हजरत अबू-अय्यूब अंसारी रजि. से रियायत है कि उन्होंने हदीस बयान की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शवाबाल के छः रोजे रखे तो मानो उसने जमाने भर के (मुसलसल) रोजे रखे। (मुस्लिम, मिशकालतुल मसाबीह- 2047), हजरत अबू-सईद खुदरी रजि बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अजहा के दिन रोजा रखने से मना फ़रमाया। (मुत्तफ़क़ अलैह, मिशकालतुल मसाबीह- 2048). आज मंगलवार रोजे का समय सहरी 05: 08 और इफ़तार 06: 27 समय है.



## राज्य के उर्दू स्कूलों में मराठी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी: प्यारे खान

> पहली कक्षा से ही छात्रों को पढ़ाई जाएगी मराठी भाषा



उर्दू स्कूलों में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। उर्दू स्कूलों के विद्यार्थियों को मराठी भाषा का भी ज्ञान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मराठी भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया जा रहा है। इस पहल के तहत रविवार को नागपुर में प्यारे खान और मराठी फाउंडेशन के शिक्षकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में उर्दू स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने तथा मराठी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में मराठी फाउंडेशन के शिक्षकों ने अपनी कई समस्याएं उठाईं। इनमें उर्दू स्कूलों में मराठी भाषा के गिरते स्तर, मराठी शिक्षकों का वेतन, उर्दू के प्रति छात्रों की घटती रुचि और मराठी के लिए गैर-मराठी शिक्षकों की नियुक्ति जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। जिसके कारण राज्य में योग्य शिक्षकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पहले महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में 4,500 से अधिक मराठी शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 500 रह गई है, जिनमें से केवल 26 शिक्षक नागपुर में कार्यरत हैं। शिक्षकों की इस कमी के कारण उर्दू स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खान ने

इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मराठी शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति पर विश्वास जताया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन उर्दू स्कूलों में अस्थायी तौर पर शिक्षक नियुक्त हैं, उन्हें जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। वहीं, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्तमान में राज्य के उर्दू स्कूलों में मराठी विषय केवल आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा में ही पढ़ाया जाता है। जिसके कारण विद्यार्थी मराठी पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। न ही वे इस विषय का ठीक से अध्ययन कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मराठी को पहली कक्षा से ही अनिवार्य कर दिया जाए। जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लाभ मिलेगा। प्यारे खान ने कहा कि राज्य में मराठी भाषा को विशिष्ट भाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे उर्दू स्कूलों के बच्चों को मराठी भाषा में भी अच्छी शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पहली कक्षा से ही मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक उर्दू स्कूल में स्थायी मराठी शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

## शेफ विष्णु मनोहर का फेसबुक अकाउंट हैक दो हजार व्यंजन और लाखों अनुयायी



फेसबुक अकाउंट हैक होने के बाद विष्णु मनोहर ने नागपुर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इस संबंध में फेसबुक की मूल कंपनी में भी शिकायत की। वे बहुत हताश थे क्योंकि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद उनका खाता वापस नहीं मिल पाया था। विष्णु मनोहर के अकाउंट पर 2,000 से अधिक व्यंजन हैं। उनके लाखों अनुयायी भी हैं। हालांकि, पिछले 10 से 12 दिनों से हैकर्स लगातार अश्लील पोस्ट कर रहे हैं और फॉलोअर्स की संख्या में कमी आने लगी है।

अश्लील बातें क्यों पोस्ट कर रहे हो? विष्णु मनोहर ने कहा, "मेरे फॉलोअर्स मुझे छोड़ रहे हैं। साथ ही कई लोग मेरे मोबाइल पर मैसेंज करके पूछ रहे हैं कि 'आप इस तरह की अश्लील पोस्ट क्यों कर रहे हैं?' उन्होंने अश्लील की है, 'इस लिंक पर क्लिक करने से आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। इसलिए प्रशासकों को इस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए।"

## विधायक मोहन मते की आरओ पानी सुविधा की मांग

नागपुर. दक्षिण के विधायक मोहन मते ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में नागपुर जिले के स्कूलों में आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि छात्रों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। विधानसभा में उन्होंने कहा कि हालांकि नागपुर जिले के 1395 स्कूलों में से 1258 में यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन शेष 137 स्कूलों में आरओ वाटर सिस्टम नहीं है। इसलिए इन स्कूलों में छात्रों को दूषित पानी पीना पड़ता है, जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों, उल्टी, बुखार, टाइफाइड और गैस्ट्रो जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में सिंद ने मांग की कि सरकार तत्काल कार्रवाई करते हुए नागपुर जिले के सभी स्कूलों में आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूलों में जल प्रबंधन पर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा सभी जरूरतमंद स्कूलों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं। विधायक मोहन मते ने विधानसभा में जोरदार मांग की कि यह छात्रों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

## महाराष्ट्र का बजट सतत विकास को गति देगा: कृपाल तुमाने

नागपुर. विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के सभी घटकों पर विचार करके भविष्य के सतत विकास को गति देने वाला बजट पेश किया है और इससे महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। आज वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश किया। प्रस्तुत बजट के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाली महायुति को बधाई। यह बजट महाराष्ट्र



के गौरवशाली इतिहास और भविष्य के विजन को दर्शाता है। महायुति राज्य के पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आश्रय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के साथ-साथ रोजगार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को

## बजट में कोई ठोस कार्ययोजना नहीं

> 2025-26 का बजट पुराने दिनों की याद दिलाता है: विधायक अभिजीत वंजारी



नागपुर. पिछले तीन वर्षों से हर साल बजट में जो योजनाएं पेश की जाती थीं, उन्हें एक बार फिर शामिल किया गया है। अब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारकों का कोई उल्लेख नहीं है। जिन प्यारी बहनों के वोट से यह सरकार चुनी गई थी, उनको चुनाव घोषणापत्र में 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन इस बजट में उसे पूरा नहीं किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि के लिए 14 अक्टूबर 2024 के सरकारी निर्णय का इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। ओबीसी तथा अन्य समान श्रेणी की जातियों और समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम की घोषणा चुनाव की पूर्व संख्या पर की गई थी, लेकिन इसे वास्तविकता में लागू करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब विद्यार्थियों की पिछले वर्ष तक बकाया लगभग 1800 करोड़ रुपए की ट्यूशन फीस

स्कूलों को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। महायुति के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार, इस बजट में राज्य के ओबीसी, एसबीसी, इंडब्ल्यूएस और वीजेएनटी छात्रों को शिक्षा और परीक्षा शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। महायुति के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार वृद्ध पेंशन भोगियों को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महायुति के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार, इस बजट में राज्य के बिजली बिल में 30% की कमी करने का कोई प्रावधान नहीं है। महायुति सारथी भारती और तरती संस्था के तहत चलने वाले छात्रों के अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कुल मिलाकर यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है और हकीकत में कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है, इसलिए वेहद निराशाजनक बजट पेश किया गया है। किसानों से लेकर प्यारी बहनों तक सभी के लिए अच्छी योजनाएं, सिंचाई के लिए वैगंगा-नलगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग, ग्राम सड़क योजना, रोजगार के लिए नए उद्योग, ग्रामीण सड़कें, मेट्रो का विस्तार, 'औद्योगिक नीति

## बजट में विदर्भ की जनता के साथ अन्याय: डॉ. राउत

बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और मजदूर विरोधी है

मुंबई/नागपुर. मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि बजट में केवल घोषणाओं की बौछार की गई है, जिसमें महंगाई पर लगाम लगाने, मध्यम वर्ग को राहत देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने या किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। विदर्भ को हमेशा विषम संतुलन मिलेगा और योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि, आज प्रस्तुत बजट में विदर्भ के मंत्री विदर्भ के लिए धन जुटाने में पूरी तरह विफल रहे। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक डॉ. नितिन राउत ने कहा कि सरकार ने विदर्भ के लिए 'शून्य बजट' दिया है, जो विदर्भ की जनता के साथ अन्याय है। आगे बोलते



हुए डॉ. राउत ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने बजट में क्यों नहीं दे, में हमेशा की तरह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की उपेक्षा की गई है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का अध्ययन किए बिना, अब तक हुए खर्चों का हिसाब किए बिना, एक-दो घोषणाओं में स्वास्थ्य के मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया। महाराष्ट्र राज्य जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे

बड़ा राज्य है। बड़ी आबादी को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और सेवाएं आवश्यक हैं। हालांकि, सरकार बजट में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की उपेक्षा कर रही है। महाराष्ट्र में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मुख्य रूप से सरकार के चिकित्सा शिक्षा और फार्मसी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि, डॉ. राउत ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार अभी भी बजट में स्वास्थ्य विभाग को धन उपलब्ध कराने में अनिच्छुक है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उम्मीद थी कि विदर्भ और मराठवाड़ा सहित राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को बजट में विशेष पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही विदर्भ विधान विकास बोर्ड को भी बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, डॉ. राउत ने कहा कि बजट ने विदर्भ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह निराशाजनक है। यह किसानों और आम जनता को निराश करने वाला बजट है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

बड़ा राज्य है। बड़ी आबादी को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और सेवाएं आवश्यक हैं। हालांकि, सरकार बजट में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की उपेक्षा कर रही है। महाराष्ट्र में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मुख्य रूप से सरकार के चिकित्सा शिक्षा और फार्मसी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि, डॉ. राउत ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार अभी भी बजट में स्वास्थ्य विभाग को धन उपलब्ध कराने में अनिच्छुक है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उम्मीद थी कि विदर्भ और मराठवाड़ा सहित राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को बजट में विशेष पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही विदर्भ विधान विकास बोर्ड को भी बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, डॉ. राउत ने कहा कि बजट ने विदर्भ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह निराशाजनक है। यह किसानों और आम जनता को निराश करने वाला बजट है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

## मेजर हेमंत जकाते इंस्टीट्यूट में 'विश्व महिला दिवस' का आयोजन

नागपुर. मनीषा शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर का संचालित मेजर हेमंत जकाते इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, म्हालगाी नगर चौक, नागपुर में 'विश्व महिला दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीषा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव मधुसूदन मुंडे सर, स्कूल प्रिंसिपल शोला मुंडे मैडम, वाइस प्रिंसिपल भारती मानकर मैडम थे। कार्यक्रम के मुख्य



प्रवक्ता के रूप में सतीश खोड़े, अपना उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पूजन कर की गई, सतीश सर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों की

भूमिका पर उत्कृष्ट मार्गदर्शन दिया। उपासे मैडम ने महिलाओं को कानून की जानकारी दी। स्कूल प्रिंसिपल शोला मुंडे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेधा पाटिल, ममता सुपारे, कल्याणी मंगरे कु मनीषा घोड़े, कु. अशिलापा इंगले को शाल व श्रीफुल से सम्मान किया। मधुसूदन मुंडे ने उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन माला चिलबुले ने व आभार प्रदर्शन कु. वंदना शहणे ने किया।

**NEW YEAR OFFER**  
Explore The Beauty Of  
**GOA**  
3 NIGHTS | 4 DAYS  
North GOA | South GOA  
MIN 06 PAX  
10% OFF  
Starting From 11,999/-  
Hotel | Meals | Taxi | Sightseeing  
Book Now  
88888 86930 | 77220 24512 | domestic@btpyatra.com | www.btpyatra.com





